लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-31 अगस्त 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -48

"जो सत्य है उसे साहसपूर्वक कहो, उससे व्यक्ति विशेष को क्या कष्ट हुआ, इस पर ध्यान न दें। : विवेकानंद

औद्योगीकरण को बढ़ावा देगी 'हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी'

3

राष्ट्रमंडल खेलों में छाया म्हारा हरियाणा

5

देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान

7

जन गण मन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पीएम के आह्वान को आत्मसात करने का संकल्प

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ-साथ आत्म-विश्लेषण करने का भी दिन है। यह दिन हमें यह सोचने का अवसर प्रदान करता है कि 75 वर्ष के इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया। निःसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज कई क्षेत्रों में पूरा विश्व हमारा लोहा मान रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरभूमि समालखा में ध्वजारोहण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज 'पांच प्रण' (विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से शत प्रतिशत मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता व एक जुटता और नागरिक

कर्तव्यों का पालन) लिए हैं, हम उन्हें आत्मसात करते हैं, प्रदेशवासियों से भी आह्वान है कि वे सभी अमृत काल के पांच प्रण के आह्वान को पूरा करने का संकल्प लें व भारत को विश्व पटल पर सबसे मज़बूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें।

सुशासन से मिली निरंतर मजबूतीः हरियाणा में गरीब परिवारों को 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए मासिक की गई हैं। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। एकल पंजीकरण व कॉमन पात्रता परीक्षा, कौशल रोजगार निगम, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण, नई शिक्षा नीति-2020, 'समर्पण' व संरक्षण योजना, 'विवादों से समाधान' 'हरियाणा हेल्पलाइन सेवा-112' और 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' जैसी अनुकरणीय पहलों से सुशासन के संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है। भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए लगभग 87 हजार युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी। 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट दिए हैं।

प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं। पंचग्राम विजन के तहत के.एम.पी. कॉरिडोर के साथ 5 नए शहर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। खरखौदा के निकट अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोहना में आई.एम.टी. भी विकसित किया जा रहा है। समान विकास की दिशा में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में 200 बैड का अस्पताल तथा कम से कम एक विश्वविद्यालय खोलना हमारा लक्ष्य है। प्रदेश के लगभग 80 फीसदी गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मानित किया।

अंत्योदय से सार्थक होता अमृत महोत्सव

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अंबाला में राज्य स्तरीय 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने एसडी कालेज अम्बाला छावनी में स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी।

राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि अम्बाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। देश पर मर-मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत-शत नमन करता हूँ।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस के जरिए व्यवस्था परिवर्तन कर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत परिवार पहचान-पत्र बनाए गए हैं। सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं को 'परिवार पहचान पत्र पोर्टल' के साथ जोड़ा जा रहा है। इस पोर्टल पर अब तक 72 लाख परिवारों का डाटा उपलब्ध हो चुका है। इसी वर्ष में अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में शिक्षा व शिक्षा से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रमों पर इस वर्ष 20,000 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं की योग्यता का सम्मान करते हुए 87 हजार से भी अधिक युवाओं को मैरिट पर सरकारी नौकरियां दी हैं। आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम' बनाया है। निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण भी लागू हो गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने प्रदेश में 33 नए महिला थाने, दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा वाहिनी की स्थापना जैसी पहल की हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है।

स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा हरियाणा

राज्य सरकार प्रदेश को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। खिलाड़ी हितैषी नीतियों के कारण राज्य के खिलाड़ी न केवल राज्य बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, जिसका जीवंत उदाहरण राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन है। इन खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के लिए 9 स्वर्ण सहित 20 पदक जीतकर अपने सर्वाधिक योगदान के साथ तिरंगे का मान बढ़ाया है। राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतकर लौटने वाले इन खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से गुरुग्राम में सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से आज हरियाणा का हर अभिभावक अपने बच्चों को खेलों में अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटियों को अब बोझ नहीं, मेडल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान में कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि म्हारे पहलवानों का डंका पूरे विश्व में बजता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने धड़ाधड़ गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख और चौथे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। कामनवेल्थ में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को साढ़े 7 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के 43 खिलाड़ियों के दल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया। व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धा में कुल 20 मेडल जीते। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड,4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया, नवीन कुमार, पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुधीर, बॉक्सर अमित पंघाल और नीतू घनघस ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं अंशु मलिक ने कुश्ती, सागर अहलावत ने बॉक्सिंग, शेफाली वर्मा ने क्रिकेट, अभिषेक और सुरेंद्र ने हॉकी में देश को सिल्वर मेडल दिलाए। पूजा सिहाग, पूजा गहलोत, दीपक नेहरा और मोहित ग्रेवाल ने कुश्ती, जैस्मिन ने बॉक्सिंग और संदीप पूनिया ने एथलेटिक्स में देश को कांस्य पदक दिलाया। महिला हॉकी टीम में सविता पूनिया, ज्योति, मोनिका मलिक, निशा वारसी, नेहा गोयल, उदिता, नवनीत, शर्मिला और सोनिका ने कांस्य पदक जीता है।

संपादकीय

33 प्रतिशत पदकों पर हरियाणवी

हम दूसरे या तीसरे स्थान पर रह सकते थे, फिर भी चौथे स्थान पर पहुंच गए। कुल स्वर्ण पदकों सहित हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश की झोली में 61 पदक तो डाल ही दिए। मलाल सिर्फ यही रहा कि कुछ बेहतर संभावनाएं अभी भी मौजूद थीं। आस्ट्रेलिया के सामने हम बौने दिखाई दिए, मगर हरियाणवी छोरों ने देश की लाज बचा ली। कुल 33 प्रतिशत पदक हरियाणवी खिलाड़ियों ने ही झटके।

इन खेलों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से थे। जाहिर सी बात है कि पदक जीतने का दबाव भी ज्यादा था। भारत ने राष्ट्रमण्डल खेलों में 22 स्वर्ण, 23 रजत समेत कुल 61 पदक जीते। इनमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। इस तरह प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 33 फीसदी पदक कब्ज़ाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलग से पदक विजेताओं को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट किया- 'बेजोड़ पीवी सिंधू चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं। वह बार-बार दिखाती हैं कि वह कितनी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। उनका समर्पण व प्रतिबद्धता प्रेरणादायी है। राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं।'

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। हर तरह के खेलों में हरियाणा का प्रदर्शन धाकड़ रहा है। प्रदेश सरकार राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित कर रही है। स्वर्ण पदक को डेढ़ करोड़, रजत पदक को 75 लाख और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपए इनाम देगी। राष्ट्रमण्डल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी साढ़े सात-सात लाख रुपए दिए जाएंगे।

अब अगली चुनौती 'ओलम्पिक' है। इसके लिए विशेष तैयारियां अभी से ही करनी होंगी।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

प्रशासनिक व्यवस्था में सुशासन सहयोगियों का अहम योगदान

सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए 'मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम' लगातार छह वर्षों से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहयोगियों के माध्यम से लगभग 50 ऐसी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका सीधा लाभ प्रदेश के ज़रूरतमंद व्यक्तियों को मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि इन फ्लैगशिप योजनाओं एवं कार्यक्रमों की देशभर में सराहना हो रही है।

इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में सहयोगियों के नए बैच का दीक्षांत समारोह हुआ। एसोसिएट्स ने सीएमजीजीए कार्यक्रम के साथ कार्य करने के अपने अनुभवों को सांझा किया और इस बारे में बताया कि उन्होंने नागरिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत बदलावों को कैसे शुरू किया।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सीएमजीजीए के परियोजना निदेशक और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने ग्रेजुएटिंग क्लास द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों की प्रशंसा की और हरियाणा सरकार तथा अशोका यूनिवर्सिटी के बीच इस संबंध में अद्वितीय सहयोग को लाभप्रद बताया।

डॉ.अग्रवाल ने कहा कि अशोका यूनिवर्सिटी के साथ सीएमजीजीए कार्यक्रम युवा पेशेवरों के लिए शासन का हिस्सा बनने और नागरिकों की सेवा करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। सीएमजीजीए मॉडल पिछले छह वर्षों में काफी विकसित हुआ है और उन्हें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे कई पूर्व छात्र नामी क्षेत्रों से जुड़े हैं और किसी न किसी तरह से समाज की बेहतरी में योगदान दे रहे हैं।

गौरतलब है कि सीएमजीजीए कार्यक्रम राज्य की प्राथमिकताओं पर कार्य करने और सुशासन के लिए युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और कौशल का लाभ उठाने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी और हरियाणा सरकार के बीच एक रणनीतिक सहयोग है, जो 2016 में शुरू किया गया था। हर वर्ष, 25 चयनित उम्मीदवारों को हरियाणा के 22 जिलों में नियुक्त किया जाता है।

-संवाद ब्यूरो

सीएमजीजीए प्रोजेक्ट अनुकरणीय

सूचना प्रौद्योगिकी के युग में नवाचार के माध्यम से प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर कार्य किया जा रहा है। गत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में हरियाणा की 'परिवार पहचान पत्र योजना' को अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने अपनाने की बात कही है। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा में टीम भेजकर इस योजना के प्रारूप और क्रियान्वयन को भी समझा है। इस प्रकार हरियाणा की बहुत सी योजनाओं की कई राज्य न केवल प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि उनका अनुसरण भी कर रहे हैं।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

औद्योगीकरण को बढ़ावा देगी हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी

हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। यह नीति मुख्यतः शहरीकरण और औद्योगीकरण उद्देश्यों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम है। चूंकि भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे, इसलिए नीति का उद्देश्य भूमि के आवंटन को रिक्त भूमि (रॉ लैंड) की लागत से जोड़कर उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करना है। नीति में विभिन्न चरणों में समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि भूमि मालिकों के हितों की सुरक्षित की जा सके और समयबद्ध तरीके से भूमि विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

क्या है उद्देश्य

» हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास सहित नियोजित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना और उक्त विकास में भागीदार बनने के इच्छुक भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से भूमि प्राप्त करना है।

» हरियाणा अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र प्रतिबंध के प्रावधानों के अनियमित विकास अधिनियम,1963 के तहत राज्य सरकार द्वारा पब्लिशड डेवलपमेंट प्लान के निर्धारित क्षेत्र के भीतर एक सेक्टर या उसके हिस्से के विकास के लिए भूमि के पूलिंग हेतू एक निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र विकसित करना है।

» इस नीति के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पब्लिशड डेवलपमेंट प्लान में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित क्षेत्रों के मामले में आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बुनियादी ढांचे का विकास करेगा।

» हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस नीति के तहत हरियाणा में कहीं भी औद्योगिक, बुनियादी ढांचे या संस्थागत उद्देश्यों के लिए विकास कार्य करेगा।

» इस नीति के तहत एचएसआईआईडीसी और एचएसवीपी के लिए उपरोक्त उद्देश्यों के अलावा राज्य सरकार किसी भी विभाग या किसी बोर्ड, निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठन को किसी भी निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ऐसा तब किया जाएगा, जब राज्य सरकार को ऐसा करना आवश्यक लगेगा।

» यह नीति निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिए परियोजना हेतू भूमि की पेशकश करने वाले भूमि मालिकों पर लागू होगी।

» यह नीति उन एग्रीगेटर पर लागू होगी, जो निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिए परियोजना हेतु भूमि की पेशकश करने के लिए कई भूमि मालिकों के साथ समझौते के तहत भूमि एकत्र करता है।

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

नीति के तहत, कोई भी भूमि मालिक, या तो सीधे या एक एग्रीगेटर के माध्यम से प्रकाशन में निर्दिष्ट अवधि, जोकि 60 दिनों से कम नहीं होगी, के भीतर विकास उद्देश्य के लिए परियोजना हेतू भूमि की पेशकश करने के लिए आवेदन जमा कर सकता है। इस अवधि को डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन यह 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। भूमि मालिक परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के विवरण के साथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे। मैन्युअल रूप से जमा किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवंटन मानदंड

भूस्वामियों को विकसित भूमि का आवंटन हिस्सा विकास संगठन के लिए परियोजना की कुल लागत में भूस्वामियों द्वारा योगदान की गई अविकसित भूमि के बाज़ार मूल्य पर आधारित होगा। भूस्वामियों को विकसित भूमि का आवंटन हिस्सा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए परियोजना की कुल लागत में भूस्वामियों द्वारा योगदान दी गई अविकसित भूमि के बाज़ार मूल्य के आधार पर होगा। विकास परियोजना के लिए योगदान करने वाले प्रत्येक भूस्वामी को वार्षिक अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे परियोजना की कुल लागत में शामिल किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत सभी भूस्वामियों द्वारा योगदान की गई अविकसित भूमि के मूल्य, विकास की लागत, अंतरिम वार्षिक सहायता और प्रशासनिक शुल्क का योग होगा।

स्वैच्छिक आवेदन

इस नीति के अंतर्गत प्रकाशन न होने की स्थित में भी भू-स्वामी या एग्रीगेटर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर राज्य सरकार को ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वेच्छा से अपनी भूमि की पेशकश कर सकता है। राज्य सरकार को इस तरह के आवेदन जमा करने के लिए कोई समय निर्दिष्ट नहीं होगा और कोई भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विकास उद्देश्यों के लिए किसी भी परियोजना हेतू प्रस्तावित भूमि का उपयोग कर सकता है। भूमि मालिक, सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से, निर्दिष्ट विकास उद्देश्य के लिए परियोजना हेतु राज्य सरकार के ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से अपने स्वामित्व वाली भूमि की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार ने वैक्सीन बना ली है जो प्रदेश के पशुपालकों को जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी।

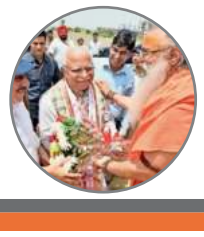

कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। जिसपर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस कार्य के लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने की घोषणा की है।

लोकसभा की तर्ज़ पर लगी ई- विधानसभा

हरियाणा विधानसभा का तीन दिन चला डिजिटल मानसून सत्र कई मायनों में अहम रहा। एक ओर, जहां सदन में इस बार विधायकों को पहले दिन टैबलेट के माध्यम से सदन की कार्यवाही का प्रशिक्षण दिया गया, दूसरी ओर विधानसभा सत्र के समय को लोकसभा की तर्ज पर प्रातः 11.00 बजे आरम्भ करके एक नई परम्परा की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं, विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए 100 रुपए में भोजन की व्यवस्था भी की गई।

याद रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वितमंत्री गत दो वर्षों से सदन में टैबलेट के जरिए ही बजट पेश किया था जो उनकी आईटी के प्रति जागरूकता दर्शाता है।

विधानसभा में सत्र के दौरान कॉमनवेल्थ खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों की सफलता का खूब जिक्र हुआ और सभी सदस्यों की ओर से उनको बधाई दी गई। खेल एवं युवा मामले राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इन खेलों में भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक हैं। कुल पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं।

सत्र के दौरान अवैध खनन और नशे के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन मुद्दों पर कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार में अवैध खनन मामलों के प्रति कड़ा संज्ञान लिया गया है जिसका परिणाम यह है कि इस दौरान राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है।

641 स्कूलों को अपग्रेड किया

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में 641 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। अपग्रेड किए गए स्कूलों में 174 प्राइमरी से मिडल, 119 मिडल से सीनियर सेकेंडरी और 348 हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 41 नए स्कूल खोले गए। राज्य में कुल 14,492 सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 2297(इन स्कूलों में 138 मॉडल संस्कृति स्कूल शामिल), उच्च विद्यालय 1037, माध्यमिक विद्यालय 2416, प्राथमिक विद्यालय 8672, आरोही विद्यालय 36, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 33 और लैब विद्यालय एक हैं।

छात्रों की संख्या पूरी होगी दोबारा खोला जाएगा : कंवर पाल ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में उन स्कूलों को बंद किया गया जिनमें छात्रों की संख्या शून्य या 25 से कम थी। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण या ग्राम पंचायत इन स्कूलों में छात्रों की संख्या पूरी करवा देते हैं तो स्कूलों को पुनः शुरु कर दिया जाएगा, जैसे इसी अवधि के दौरान 66 स्कूल बंद होने के बाद दोबारा शुरू किए गए हैं। प्राइमरी स्कूल 179 व मिडल स्कूल 17 हैं । कुल मिलाकर 196 स्कूल बंद हुए हैं ।

अध्यापकों के पद भरे जाएंगेः कंवर पाल ने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों के 7649 पदों को भरने के लिए आयोग को आग्रह भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले शैक्षणिक सत्र के अनुसार प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक , पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के कुल 1,26,136 पदों की आवश्यकता है, जिसमें से 90,156 पद भरे हुए हैं।

पालिका की सीमा में काम करने से पहले लेनी होगी अनुमति

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया है। अधिकांश नगरपरिषदों के क्षेत्रफल व जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जिससे कार्यों एवं निगरानी का दायरा कई गुणा बढ़ गया है। इसलिए नगरपरिषद का सम्पूर्ण कार्य एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को सौंपे जाने की आवश्यकता है, जो इन नगरपरिषदों के कार्यो को कुशलता एवं समयबद्धता तरीके से कर सके। इसलिए संबंधित जिला नगर आयुक्त , जिला मुख्यालय की नगरपरिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा संबंधित मंडल आयुक्त को जिला मुख्यालय की नगरपरिषद के मामले में अपीलीय तथा अन्य शक्ति यां जो कि वर्तमान में जिला नगर आयुक्त के पास हैं, सौंपी जाएंगी।

पशुओं एवं पक्षियों को पालिकाओं की सीमा में रखने एवं पालने की पाबंदियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत चौपाया पशुओं या पक्षियों को समिति की सीमाओं के भीतर रखने या पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परंतु समिति से अनुमति उपरांत किसी बिल्ली, कुत्ता या पक्षी को पालतू के रूप में रखा जा सकेगा।

नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर 1 से 3 प्रतिशत तक शुल्क लिया जाएगा। किसी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर चर्बी पिघलाना, कच्चा चमड़ा साफ करना, हड्डियां या रक्त उबालना, साबुन के कारखाने, तेल उबालने के कारखाने, चर्मशोधन के कारखाने, ईंट भट्टे, मिट्टी के बर्तनों के कारखाने, भण्डार या कारोबार के ऐसे स्थान, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों या जिनसे गंद, गैसें या धुआं निकलता हो ऐसी इकाइयां निषेध होंगी।

इसके अतिरिक्त , अनबुझा चूना, सूखी घास, लकड़ी, काठ, कोयला या अन्य खतरनाक सामग्री में व्यापार करने के लिए डिपो, किसी विस्फोटक के लिए या पैट्रोल या स्प्रिट के लिए भण्डार गृह निषेध होगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, तो उसे 6 महीने कारावास या कम से कम 1000 रुपये और अधिक से अधिक 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा।

किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति समिति की अनुमति लिये बिना किसी नये कारखाने या कर्मशाला की स्थापना नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा, तो उसे कम से कम 2,000 रुपए और अधिक से अधिक 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। यदि दण्ड के बाद भी व्यक्ति इसे चालू रखता है, तो अतिरिक्त जुर्माने के रूप में उसे 1,000 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड वहन करना होगा।

किसी सिनेमेटोग्राफ अथवा अन्य चित्रों, जिनके प्रयोजन के लिए ज्वलनशील फिल्में उपयोग में लाई जाती हैं, किसी नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे परिसरों को अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 2,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। पहले से बने भवनों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए संबंधित नगरपालिका समिति से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

ये विधेयक हुए पारित

» हरियाणा विधान सभा सत्र में जो विधेयक पारित हुए उनमें हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन तथा प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक, हरियाणा माल और सेवा कर विधेयक, हरियाणा नगर निगम विधेयक तथा हरियाणा नगरपालिका विधेयक शामिल हैं।

» हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अधिनियम-2020 की धारा-18 में संशोधन किया गया है। अब प्राधिकरण द्वारा बल्क और उपचारित अपशिष्ट जल के लिए शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। संशोधन के अनुसार, प्राधिकरण मितव्ययता, दक्षता, समानता और स्थिरता के सिद्धांतों और सतही जल और उपचारित अपशिष्ट जल के अत्यधिक मात्रा में उपयोग के लिए दरें तय करेगा। ये दरें पानी की खपत के आधार पर तय होंगी। प्राधिकरण व्यक्ति गत घर, उद्योग या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए पानी के उपयोग के हिसाब से पानी की खुदरा दरें भी तय करेगा।

» हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया है।

» हरियाणा नगर निगम विधेयक, 1994 की धारा 330, 331, 335, 336 तथा 352 के साथ द्वितीय और तृतीय अनुसूची में संशोधन किया गया है। वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया कि पालिका क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के पंजीकरण पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क सम्बन्धित नगर निगम या शहरी स्थानीय निकाय विभाग को एक-एक प्रतिशत की दर से समान रूप से सीधे तौर पर स्थानांतरित किया जाएगा।

» हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की सम्बन्धित धाराओं में व्यापार/व्यावसायिक लाइसेंस प्राप्त करने व इनके वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करवाने का प्रावधान है। राज्य के सभी नगर निगमों में व्यापार/व्यवसायिक लाइसेंस फीस की दर निर्धारित करने में एकरूपता लाने तथा इनकी अनिवार्यता को सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रयोजन, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हों या जिससे उत्पात उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तक लागू रखने की अति आवश्यकता है। यह नियामक प्राधिकरणों की बहुलता को समाप्त करके शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को आसान करेगा।

» हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए पारित किया गया है।

» चूंकि जीएसटी कानून केन्द्र सरकार तथा राज्यों द्वारा समान रूप से लागू किया जाता है, इसलिए वित्त अधिनियम, 2022 में पहले से ही हो चुके संशोधन की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन अपेक्षित था।

» हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रावधान किया गया है कि किसी आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ केवल तभी लिया जा सकेगा, जब ऐसे 'क्रेडिट को धारा 38 के अधीन करदाता को संसूचित ब्यौरों में निबंधित न किया गया हो।

डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मरम्मत हेतु 80 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। अब तक 2,270 लाभार्थियों को 4,235 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान से करनाल तथा आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यहां प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के व भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राष्ट्रमंडल खेलों में छाया

इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में देश के

संगीता शर्मा

22वें राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन बरकरार रखा । भारत को कुल 61 पदक दिलाने में कुल 107 खिलाड़ियों का योगदान रहा। इनमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं, राष्ट्रमंडल खेलों में कुल पदक में से लगभग 33 प्रतिशत भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की रही। प्रदेश के 43 खिलाड़ियों के दल ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया और 20 पदक देश को दिलवाए। जिसमें से 9 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें 17 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक हासिल किए जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम में दो खिलाड़ियों और भारतीय महिला हॉकी टीम में नौ खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। इसके साथ ही एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहा है।

खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन करने में हरियाणा सरकार की नई खेल नीति का विशेष योगदान है। खिलाड़ियों के लिए खेल नर्सरी, अच्छी डाइट, खेलों का उच्चतम दर्जे का आधारभूत ढांचा, छात्रवृत्तियां, नौकरियां व विजेताओं को ढेरों ईनाम राशि ने युवाओं का रूझान खेलों की ओर बढ़ाया है। अभिभावक लड़कियों को भी कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी व अन्य खेलों में प्रेरित कर रहे हैं ताकि वे अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ 50 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख और चौथे स्थान पर आने वाले को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ-साथ राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को साढ़े सात लाख रुपए की राशि दी जा रही है।

नौ स्वर्ण पदक हासिल किए

कुश्ती में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट, नवीन कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। बॉक्सिंग में अमित पंघाल व नीतू घनघस स्वर्ण पदक, पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने स्वर्ण पदक हासिल किया। रजत पदक विजेताओं में कुश्ती में अंशु मलिक, महिला क्रिकेट टीम में शेफाली वर्मा, बॉक्सिंग में सागर, पुरुष हॉकी टीम में सुरेंद्र कुमार व अभिषेक शामिल रहे। कुश्ती में पूजा गहलोत, पूजा सिहाग, दीपक नेहरा और मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता। बॉक्सिंग में जैसमिन लंबोरिया, एथलेटिक्स में संदीप पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। महिला हॉकी टीम में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया है। टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। 18 सदस्यीय हॉकी टीम में 9 महिलाएं सविता पूनिया, ज्योति, मोनिका मलिक, निशा वारसी, नेहा गोयल, उदिता, नवनीत, सोनिका व शर्मिला हरियाणा की हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय उनकी मेहनत, अभिभावकों के परिश्रम और त्याग तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खेल प्रेम नीति को जाता है। जिसकी बदौलत हरियाणा केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व में खेल हब के रूप में उभर कर सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से आज हरियाणा का हर अभिभावक अपने बच्चों को खेलों में अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटियों को अब बोझ नहीं, मेडल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है।

संदीप सिंह, खेल एवं राज्य युवा मंत्री, हरियाणा

खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन कियाः सीएम

राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी गदगद हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार लट्ठ गाड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि म्हारे पहलवानों का डंका पूरे विश्व में बजता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति का ही परिणाम है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने धड़ाधड़ स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में शामिल हरियाणा के खिलाड़ियों ने ना केवल खुद को साबित किया है बल्कि पदक तालिका को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि अपनी मेहनत के बलबूते पर इन सभी खिलाड़ियों ने देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है।

बजरंग पूनिया

सोनीपत के बजरंग पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती स्वर्ण पदक हासिल करके राज्य का नाम रोशन किया। बजरंग पूनिया बचपन में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। वह स्कूल से बचने के लिए अखाड़े जाने लगे। वहां कुश्ती जीतने पर मिलने वाले इनाम से उन्हें प्रोत्साहन मिला और वह पहलवान बन गए। बजरंग का कहना है कि हरियाणा सरकार खेलों व खिलाड़ियों को बढ़ावा देने बहुत अच्छा प्रयास कर रही है।

साक्षी ने सच किया सपना

रोहतक की पहलवान साक्षी मलिक दो मुकाबलों के लिए उतरीं और दोनों में विजेता रह कर देश को स्वर्ण पदक दिलाया। साक्षी मलिक तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में गई हैं। इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम और ओलिंपिक में केवल कांस्य और रजत पदक ही जीत पाई थीं। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में उनका स्वर्ण पदक जीतने का सपना पूरा हुआ। अब अगला लक्ष्य एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीतना है।

बहन के नक्शे कदम पर विनेश

बलाली गांव की विनेश अपनी चचेरी बहन गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चल रही है। उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने बहुत ही कम उम्र में उनको कुश्ती के दांव-पेंच सिखाने शुरू कर दिए थे। सोनीपत की बहू विनेश फोगाट दो बार ओलिंपिक खेल चुकी हैं। राष्ट्रमंडल खेल में 2 स्वर्ण पदक, एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक उनके नाम है। उनकी शादी 13 दिसंबर 2018 को सोनीपत के फरमाना गांव के

राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की नई वेबसाइट और ब्रांड पहचान इसकी मार्केट लीडिंग पॉजिशन को बेहतर ढंग से दर्शाती है और ग्राहकों के लिए सेवाओं के व्यापक चक्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

परिवार पहचान पत्र

परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर अब तक 70 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हो चुका है, इसमें राज्य की 2.76 करोड़ आबादी कवर हो जाती है। लगभग 86 प्रतिशत परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है।

म्हारा हरियाणा

क खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

किस खेल में कितने पदक 2022

खेल	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
कुश्ती	6	1	5	12
टेबल टेनिस	4	1	2	7
वेटलिफ्टिंग	3	3	4	10
बॉक्सिंग	3	1	3	7
बैडमिंटन	3	1	2	6
एथलेटिक्स	1	4	3	8
लॉन बॉल्स	1	1	0	2
पैरा पावरलिफ्टिंग	1	0	0	1
जूडो	0	2	1	3
हॉकी	0	1	1	2
क्रिकेट	0	1	0	1
स्क्वॉश	0	0	2	2
कुल	22	16	23	61

पहलवान सोमबीर राठी से हुई है।

रवि ने दस साल की उम्र में रेसलिंग शुरू

नाहरी गांव में जन्में रवि दहिया ने कुश्ती में नाइजीरिया के वेल्सन को हरा कर स्वर्ण पदक जीता। फिलहाल दिल्ली में आप सरकार में एजुकेशन डायरेक्टर हैं। टोक्यो ओलिंपिक 2020 में कांस्य पदक जीत चुके हैं। दस साल की उम्र मे ही रवि ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में रेसलिंग शुरू कर दी थी।

नेवी के हवलदार ने जीता स्वर्ण पदक

पुगथला के नवीन कुमार मलिक ने कुश्ती में पाकिस्तान के पहलवान मो. शरीफ ताहिर को धूल चटा स्वर्ण पदक जीता। नवीन खेल कोटे से इंडियन नेवी में हवलदार है और 19 साल की आयु में पहला राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। तीन साल की उम्र मे ही नवीन ने लंगोट बांध कर अखाड़े में आना शुरू कर दिया था।

सुधीर ने पिता के नाम किया पदक

लाठ गांव के पैरा खिलाड़ी सुधीर ने पावर लिफ्टिंग में देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। जींद में पावर लिफ्टिंग के सीनियर कोच सुधीर ने जीत के बाद अपना मेडल पिता राजबीर सिंह के नाम किया।

दीपक की मेहनत रंग लाई

झज्जर जिले के गांव छारा निवासी पहलवान दीपक पूनिया ने कुश्ती रेसलिंग में स्वर्ण पदक देश की झोली में डाला। दीपक पूनिया ने 86 किग्रा. फ्री-स्टाइल कुश्ती में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम बट्ट को 3-0 से मात दी। दीपक के पिता सुभाष पूनिया एक डेयरी किसान हैं। दीपक ने अपने कुश्ती करियर की शुरुआत पांच साल की उम्र में अपने गृहनगर अर्जुन अवार्डी वीरेंद्र सिंह छारा के नेतृत्व वाले एक अखाड़े में की थी।

माता-पिता के आशीर्वाद से मिली जीत

रोहतक के बॉक्सर अमित पंघाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। अमित के पिता विजेंद्र सिंह ने कहा कि बेटे ने दिखा दिया है कि वो दुनिया का नंबर-1 बॉक्सर है। अमित का मानना है कि माता-पिता के आशीर्वाद से उन्हें यह जीत मिली। इसलिए वे हर मुकाबले में जाने से पहले माता-पिता से बात करना नहीं भूलते।

21 साल की अंशु का पहला राष्ट्रमंडल

गांव निडानी की पहलवान अंशु मलिक मात्र 21 वर्ष की हैं। वे पहली बार राष्ट्रमंडल में खेलने गईं और रजत पदक लेकर लौटी हैं। अंशु मलिक 2018 के टोक्यो ओलिंपिक में पहले ही राउंड में हार गई थीं। उनके पिता धर्मवीर मलिक भी अंतरराष्ट्रीय पहलवान रह चुके हैं।

स्वर्ण पदक विजेता

बजरंग पुनिया, कुश्ती · साक्षी मलिक, कुश्ती · दीपक पुनिया, कुश्ती · विनेश फोगाट, कुश्ती · नवीन मलिक, कुश्ती · रवि कुमार दहिया, कुश्ती · नीतू घनघस, बॉक्सिंग · अमित पंघाल, बॉक्सिंग · सुधीर, पैरा पावर लिफ्टिंग

रजत पदक विजेता

अंशु मलिक, कुश्ती · सागर, बॉक्सिंग · सुरेंद्र कुमार, पुरुष हॉकी टीम · अभिषेक, पुरुष हॉकी टीम · शेफाली वर्मा, महिला क्रिकेट टीम

पूजा ने जीता कांस्य पदक

गांव फरमाना की पूजा गहलावत ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटगरी में कुश्ती में कांस्य पदक वर्ग जीता। उनके चाचा धर्मवीर सिंह एक पहलवान थे और उनके देखा-देखी वे छह साल की उम्र से ही अखाड़े में खेलने लगी थी।

रोज़ाना अभ्यास से सफलता

निंदाना गांव के पहलवान दीपक नेहरा ने कुश्ती में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। दीपक नेहरा पिछले करीब 12-13 सालों से कुश्ती कर रहे हैं। दीपक के पिता सुरेंद्र ने कहा कि जब वे करीब पांच-छह साल के थे तो उन्हें अखाड़े में कुश्ती के लिए भेज दिया था। दीपक नेहरा ने राष्ट्रमंडल खेल के लिए हर रोज करीब आठ घंटे पसीना बहाया।

महिला हॉकी में कांस्य पदक

राष्ट्रमंडल खेल में गई भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ी हैं। इनमें नेहा गोयल, सविता पूनिया, मोनिका, सोनिका, शर्मिला, उदिता, निशा, ज्योति और नवनीत कौर शामिल हैं। इनमें से ज्योति, नेहा गोयल, निशा वारसी और मोनिका मलिक सोनीपत से हैं। कोच प्रीतम सिवाच ने कहा कि 16 साल बाद महिला हॉकी टीम का कांस्य पदक आया है।

कांस्य पदक विजेता

जैसमिन लंबोरिया, बॉक्सिंग · संदीप पूनिया, पैदल यात्रा · दीपक नेहरा, कुश्ती · पूजा सिहाग, कुश्ती · पूजा गहलोत, कुश्ती · मोहित ग्रेवाल, कुश्ती · सविता पूनिया, महिला हॉकी टीम · नेहा गोयल, महिला हॉकी टीम · मोनिका, महिला हॉकी टीम · शर्मिला, महिला हॉकी टीम · नवनीत कौर, महिला हॉकी टीम · निशा, महिला हॉकी टीम · ज्योति, महिला हॉकी टीम · उदिता, महिला हॉकी टीम · सोनिका, महिला हॉकी टीम

महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ़ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। यदि लाभार्थी भुगतान एकमुश्त या छह किस्तों में एक दिसंबर, 2022 तक वापिस करता है तो उसका ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा।

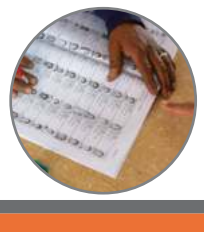

17 वर्ष से अधिक के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज़ कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्वापेक्षित मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

किसान हितैषी किसान कल्याण प्राधिकरण

सामूहिक खेती पर 90 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान

किसानों के कल्याण एवं उनकी आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें राज्य के मंत्री, आईएएस अधिकारी व विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शामिल किया गया है। प्राधिकरण में अलग-अलग फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पांच छह किसानों का एक समूह बनाया जाएगा। इस प्रकार से लगभग छह-छह किसानों के अलग-अलग समूह बनाए जाएंगे। यह किसानों के समूह कृषि क्षेत्र में सुधार व आय बढ़ाने संबंधी सुझाव सरकार को देंगे और सरकार उनके सुझाव को क्रियान्वित करने का काम करेगी।

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण को खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द विजन डॉक्यूमेंट-2047 तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ-साथ प्राधिकरण, किसान कल्याण के लिए खेती से जुड़ी अलग-अलग कमेटियों का भी गठन के लिए कहा गया है, ताकि इनके सुझावों को भविष्य में सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा सके।

संबंधित कमेटियां क्षेत्रों पर गहनता से कार्य

किसान प्राधिकरण एक सुपर थिंक टैंक का काम करेगा। इसके तहत खारा पानी, जल भराव, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, मशरूम फॉर्मिंग, आर्गेनिक खेती, माइक्रो इरिगेशन आदि विषयों पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा इन अलग-अलग कमेटियों में संबंधित क्षेत्रों के शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, राष्ट्रीय अवार्डी किसानों आदि को शामिल किया जाएगा। ये कमेटियां संबंधित क्षेत्रों पर गहनता से कार्य करेगी और सरकार को सुझाव देगी ताकि किसानों की आमदनी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और बेहतर फसल ली जा सके।

> हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण खेती के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनके स्किल डेवलेपमेंट से जुड़े सुझाव भी दें, ताकि किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। किसानों के हित के लिए ही इस प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें सरकार के सदस्यों के साथ-साथ खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि के विशेषज्ञों को सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है।
>
> **मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीजीआईएमएस रोहतक के ऑडिटोरियम में आयोजित 'जय किसान कार्यक्रम' में फसल विविधिकरण को अपनाकर उदाहरण प्रस्तुत करने वाले किसानों को सम्मानित करने के बाद कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का मकसद कृषि को बढ़ावा देना और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। भविष्य में किसानों द्वारा साझा किए गए सभी प्रमुख सुझावों को राज्य की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। सामूहिक खेती करके अधिक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। सामूहिक खेती पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसान ऋण भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कृषि उत्पाद बेचना भी एक कला है और किसान अपने उत्पाद बेचना सीख लेगा तो आमदनी स्वयं बढ़ जाएगी।

दूसरे राज्यों की अच्छी नीतियों को करेंगे लागू

राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कोई भी अच्छी नीति को लागू करने के लिए तैयार है। अगर किसी राज्य में किसी को लेकर कोई अच्छी नीति अथवा तकनीक अपनाई जा रही है तो इसकी जानकारी सरकार को दें। सरकार अधिकारियों को भेज कर इसका अध्ययन करवाएगी और उसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

झींगा पालन में लाखों की आमदनी

हरियाणा में आठ से दस लाख एकड़ खारे पानी की भूमि है। ऐसे ही भूमि में झींगा मछली पालन करके लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। सरकार इसके लिए प्रशिक्षण व रियायतें दे रही है। सरकार ने सेमग्रस्त भूमि का पानी निकाल कर उसे ठीक करने की योजना भी क्रियान्वित की है। एक वर्ष में एक लाख एकड़ भूमि को ठीक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान पशुपालन के माध्यम से भी जल्दी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने अपना ध्यान पशुओं की नस्ल सुधारने पर केंद्रित किया है ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। मात्र 100 रुपए दो प्रीमियम पर पशु बीमा योजना लागू की गई है।

राज्य सरकार ने बढ़ाया कृषि बजट

'पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना' भी प्रदेश में क्रियान्वित की गई है। योजना के तहत चार प्रतिशत ब्याज की दर से 1 लाख 60 हजार रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है। भेड़-बकरी व सूअर पालन में भी बहुत लाभ है। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार ने अलग से मंडी बनाने का भी निर्णय लिया है। प्राकृतिक खेती के लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

उपज खरीदने में न हो एकाधिकार

राज्य सरकार चाहती है कि किसानों की उपज को खरीदने पर किसी का एकाधिकार ना हो। किसान की उपज को खरीदने के लिए एक से अधिक खरीदार मिले ताकि उन्हें न तो मंडियों में टैक्स देना पड़े और दाम भी अच्छे मिल सके। किसान अपनी मर्जी से अपने उत्पाद बेच सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पानी का संकट है। इसलिए किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाना चाहिए। इसके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ खेतों में तालाब बनाने के लिए भी किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है।

किसानों को सम्मानित किया

कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इससे पहले परंपरागत खेती को छोड़कर फसल विविधिकरण करने वाले किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी सम्मानित हुए किसानों से प्रेरणा लेकर कार्य करने चाहिए। कृषि मंत्री ने जिन किसानों को सम्मानित किया उनमें पलवल के श्यामसुंदर, फतेहाबाद के हरि समाधान, गुरुग्राम के अशोक कुमार, मेवात के जयदेव, हिसार के रामफल, झज्जर के नीतिन, कैथल के विजय शर्मा, नारनौल के अनिल कुमार, पानीपत के जसवीर सिंह, रोहतक के रामभज ढाका, रेवाड़ी के अनिल कुमार, सोनीपत के रवि कुमार, हिसार के शिव शंकर, पानीपत के रामप्रताप, कुरुक्षेत्र के कुसुम, झज्जर के जगपाल फोगाट, जींद के सुमेर सिंह, कुरुक्षेत्र के हरविंदर तथा पंचकूला के बलविंदर शामिल है।

-संवाद ब्यूरो

बाजरे को 'न्यूट्री-सेरिअल' के रूप में प्रचारित करेगी सरकार

संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय 'न्यूट्री-सेरिअल' वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को 'न्यूट्री-सेरिअल' के रूप में प्रचारित करेगी। हरियाणा में लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है तथा उत्पादन भी प्रति एकड़ लगभग आठ क्विंटल तक होता है। यह जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारी कमेटी की बैठक में दी गई।

अनुबंध खेती करवाने के करें प्रयास

मुख्य सचिव ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बासमती चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए सीधे कंपनियों से अनुबंध खेती करवाने के प्रयास करें। बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई कि हैफेड संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई) व अन्य अरब देशों के साथ बासमती चावल का निर्यात पहले से ही कर रहा है।

कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जौ की अनुबंध खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए। इसके अलावा, कपास की फसल पर संभावित 'पिंक वार्म' के प्रकोप से बचने के लिए भी अभी से ही अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में 'पिंक वार्म' आने की जानकारी मिल रही है। बैठक में राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत रबी 2007-08 से आरम्भ किया था। इसके तहत दलहन एवं तिलहन की पैदावार को बढ़ावा देना था। वर्ष 2018-19 में खाद्य तेल एवं पाम ऑयल को शामिल किया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्र सरकार ने इस मिशन के लिए 4,013.86 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की थी, जिसके अन्तर्गत किसानों को प्रमाणित बीज, कलस्टर प्रदर्शन खेत, माइक्रोन्यूट्रेंट, कृषि मशीनरी, समेकित कीट प्रबंधन तथा फसल एवं मृद्धा सुरक्षा प्रबंधन के लिए सब्सिडी दी जाती है।

प्रदेश के अस्पतालों में जल्द ही पुरुषों के साथ-साथ महिला फीजियो-थैरेपिस्ट भी रखी जाएंगी। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक आयुर्वेदिक डाक्टर की नियुक्ति भी करेगी।

फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सैंटर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश की विकास रिपोर्ट

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को साकार करते हुए सतत आर्थिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में नीति आयोग की तरफ़ से विश्वास दिलाया गया कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन करने के लिए आयोग राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगा। वहीं, देश का इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने की दिशा में भी नीति आयोग ने राज्यों को विश्वास दिलाया ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 74 हजार 635 रुपए है, जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। आर्थिक विकास के मानदंडों पर भी हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक लगातार छह प्रतिशत से अधिक है। मैनुफैक्चरिंग की विकास दर दस प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। विश्व की 400 फॉरच्यून कंपनियों के कार्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक राज्य है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे तथा उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। हरियाणा का आधे से ज्यादा क्षेत्र एनसीआर में आता है। हम इस क्षेत्र में उद्योग व व्यापार को बढ़ाने के लिए इसे लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं।

बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। केंद्रीय खाद्यान्न पूल में लगभग 15 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1.34 प्रतिशत है। हमारी कृषि विकास दर लगभग 3.3 प्रतिशत वार्षिक है। प्रदेश में उत्पादकता अत्यधिक है, जोकि प्रति हैक्टेयर एक लाख 57 हजार रुपए है। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहां किसान की आय बढ़ रही है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में बागवानी और पशुपालन का शेयर बढ़ रहा है। प्रदेश में नवीन तकनीक और फसल विविधिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। धान की जगह अन्य फसलें बोने पर 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना में 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। डी.बी.टी. के माध्यम से 74,133 किसानों के खातों में 76 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डाली गई है। बाजरे की जगह दलहन-तिलहन की खेती पर 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मक्का में 62 हजार 500 एकड़ और दलहन में 32 हजार 500 एकड़ क्षेत्र में विविधिकरण हुआ। धान की बिजाई पर भी 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर राशि दी जा रही है। इससे 25 से 30 प्रतिशत तक पानी की बचत हो रही है।

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए विशेष योजना

हरियाणा पहला राज्य है जिसने ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ खजूर की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसमें ड्रैगन फ्रू ट के लिए तीन लाख रुपए प्रति हैक्टेयर की सब्सिडी प्रदान की जाती है। मनोहर लाल ने कहा कि फलों व सब्ज़ियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त करने के लिए 'भावांतर भरपाई योजना' चलाई जा रही है। इसमें 21 बागवानी फसलों के अलावा बाजरा भी शामिल है। वहीं, बागवानी किसानों को मौसम की अनिश्तिताओं के जोखिम से भी मुक्त करने के लिए 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' शुरू की गई है। इसमें बागवानी की 21 फसलें शामिल है।

50,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खातों में डाली

'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल से किसानों को उनकी उपज के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खातों में डाली गई। उपज का भुगतान भी 72 घंटे के भीतर न करने पर 9 प्रतिशत ब्याज दिया गया। बीज विक्रेताओं की मनमानी रोकने के लिए उत्तम बीज पोर्टल शुरू किया गया। मशीनरी पर सब्सिडी के लिए ई-रुपे वाउचर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में मांग आधारित विविधिकरण की आवश्यकता है। खेती को जितना बाजार से जोड़ा जाएगा और बाजार की मांग के अनुसार विविधिकरण किया जाएगा, उतनी ही आय बढ़ेगी।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

हरियाणा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता में देश में दूसरे स्थान पर है। 'किसान क्रेडिट कार्ड' की तर्ज़ पर 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड' जारी किया जा रहा है। 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना' के तहत 3 लाख 40 हजार पशुओं का बीमा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन में संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। राज्य में 12 रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम व 20 बायोफलक यूनिट की स्थापना की गई है। वर्ष 2021-22 में 2.09 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया गया। वर्ष 2022-23 में 2.10 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021-22 में 1250 एकड़ क्षेत्र में 2901 मीट्रिक टन सफेद झींगा मछली का उत्पादन किया। गोबर व कृषि अवशेषों से भी आय के लिए बायोगैस को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और किसानों को इस बारे में प्रोत्साहित किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य

मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में एक कि.मी. में प्राथमिक, तीन कि.मी. में माध्यमिक विद्यालय मौजूद है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए मुफ़्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम के तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों की स्थापना की गई है। मेधावी विद्यार्थियों को मुफ़्त कोचिंग हेतु सुपर-100 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबन्ध करने के 10वीं-12वीं के पांच लाख विद्यार्थियों को मुफ़्त टेबलेट वितरित कि गए हैं।

सर्विस डिलीवरी के लिए आई.टी. का उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीकृत जीआईएस आधारित सम्पत्ति कर सर्वेक्षण में 42 लाख सम्पत्तियों का सर्वे किया गया है। प्रदेश में नो ड्यूस सर्टिफिकेट के लिए एनडीसी पोर्टल शुरू किया गया है। सम्पत्ति आई.डी. को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। विज्ञापन स्थलों की ई-नीलामी के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। 2 हजार से अधिक कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 114 तालाबों का अमृत सरोवर योजना में जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। सर्विस डिलीवरी के लिए आई.टी. का उपयोग किया जा रहा है। 35 शहरों में सर्विस प्लस प्लेटफार्म द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नगरनिकायों के लाल डोरा में भी स्वामित्व अधिकार देने की योजना पर काम किया जा रहा है।

महाराजा अग्रसेन मेडिकल कालेज, अग्रोहा, हिसार की चिकित्सा शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान सोसायटी की कार्यकारी कमेटी की बैठक में 172.51 करोड़ के कैपीटल प्रोजेक्ट एग्रीमेंट की अवधि को विस्तार देने की मंजूरी दी गई है।

हरियाणा में ग्रुप- सी एवं डी के लगभग 28,000 पदों की भर्ती के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) 5, 6 और 7 नवंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी। सीईटी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया है।

विभाजन का दंश झेलने वाले बुजुर्गों से मिले मनोहर लाल

शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र में बनेगा शहीदी स्मारक

देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में कुरुक्षेत्र जिले के पिपली के नजदीक शहीदी स्मारक बनाया जाएग जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आह्वान किया कि समाज का हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार इसमें योगदान दे। वे भी इस ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते इसमें भरपूर सहयोग देंगे।

कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्व प्रथम सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग व हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी द्वारा लगाई गई दो प्रदर्शनियों का उद्घाटन व अवलोकन किया। इन प्रदर्शनियों में विभाजन के दौरान की यादों को तस्वीरों, कार्टून व खबरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने मंच से नीचे आकर विभाजन विभीषिका को झेलने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के मंच से नीचे आकर सम्मानित करने पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। ऐसे में बुजुर्ग भी भावविभोर हो गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए, यह खुशी का दिन रहा लेकिन 14 अगस्त खुशी का दिन नहीं हो सकता क्योंकि इस दिन देश के बंटवारे की लकीर हमारे अरमानों पर खींची गई थी। यह भूमि का बंटवारा नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का बंटवारा था। आज देश इस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मना रहा है। इस बंटवारे में पंजाब, बंगाल और

सिंध प्रांत अलग हो गए। इससे पहले देशों के बंटवारे तो बहुत हुए लेकिन यह पहला बंटवारा था जिसमें लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और लोग शहीद हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को आजादी से पहले विभाजन का दंश झेलना पड़ा। अपना-अपना क्षेत्र छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर बसना पड़ा। मुख्यमंत्री ने एक शेर सुनाकर इस त्रासदी को बताया कि 'वहां से चले तो पता नही था, बेबसी सी जिंदगी ने देखा था हमें, हम सफर पर थे पर मंजिल कहां है पता न था'। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय कुछ लोग 15 अगस्त को तो कुछ 16 व कुछ 17 अगस्त को चले थे। कुछ पैदल, कुछ ट्रेन व कुछ बैलगाडियों में यहां तक आए। मजहबी उन्माद, हिंसा, नफरत की वजह से विभाजन में लाखों लोग शहीद हो गए। कुछ लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बहू-बेटियों को तलवार से काट डाला। इतना ही नहीं विभाजन के समय इज्जत बचाने के लिए बहू-बेटियों ने कुएं में छलांग लगा दी थी। इन घटनाओं को कुछ पुराने लोग याद करते हैं तो उनके रौंगटे खड़े हो जाते हैं।

शरणार्थी नहीं, पुरुषार्थी है समाज

मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के समय जब लोग यहां आए तो उनके समक्ष खाने तक के लाले पड़े हुए थे लेकिन उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लोग मेहनत, परिश्रम और कौशल के दम पर अपने पैरों पर खड़े हुए और पुरुषार्थ कर देश की तरक्की में मील के पत्थर बने। इसलिए यह समाज शरणार्थी नहीं बल्कि पुरुषार्थी है। आजादी के बाद 70 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए लेकिन किसी ने भी विभाजन विभीषिका के शहीदों को याद नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष लाल किले से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की।

-संवाद ब्यूरो

सुण छबीले बोल रसीले

दस मिनट में पुलिस की मदद

रसीले आज तड़के-तड़क के रौला-सा कर रे सो?

छबीले रौला कोन्या कर रे। रौला तो रात नै हो लिया।

- के बात होई, सब ठीक-ठाक तो सैं?

- भाई, दो दिन होगे गाम में चोरां का पड़गड़ास पाटर्‌या सै।

- आच्छा रै, के बात होई?

- परसों रात नै एक बदमाश आपणे घर में बड़ण की कोशिश करै था।

-आच्छा फेर के होया, बड़ग्या?

- क्यानैं, पकड़कै सीधा कर दिया।

- न्यू होया, रात नै करीब एक बजे वो अनजान माणस सड़क-सड़क आया और पछीत में बाबू की समाध कान्या बड़ग्या। स्यामी मकान में तै नंबरदारणी नै वो देख लिया। पूछ्या अक कुणसा सै। पर वो बोल्या कोन्या, उड़ैए लुकण की कोशिश करण लाग्या। नंबरदारणी गेल्यां गेल्यां चुपके तैं म्हारे बारणै आई और गेट खुड़काया।

- हामनै सोची, हो सकै सै

नंबरदारां कै कुछ परेशानी होगी हो। गेट खोल दिया और पूछा- नंबरदारणी सब ठीक-ठाक तो सैं। नंबरदारणी ने बताया अक हाम तो सब ठीक सैं। पर बाहर सब ठीक कोन्या। समाध कान्या कोए माणस बड़्या सै। रुक्का दिया तै वो उड़ै लुकग्या।

- आच्छा, न्यू बात सै। भोलू की मां तावली उठ, कोए ओपरा माणस सै। छोरे नै जगाल्या।

छबीले, हाम लाठी ठाकै चाल पड़े। उड़ै जाकै देख्या तो बात साची पाई। माणस था। कई बै आवाज़ दी, बोल्या कोन्या। इतणे में छोरे नै 112 नंबर पै डायल कर दिया।

मनैं देख्या उस माणस के हाथ में आच्छी मोटी लाठी थी। मोबाइल हाथ में लेर्‌या। रुक्का दें, पर बोलै कोन्या। पांच-चार मिनट ताहीं कोशिश करी पर वो बोल्या कोन्या। फेर वो उड़े तैं लिकड़ण की कोशिश करण लाग्या। मनैं नजर-सी बचाकै उसकी टांगा पै एक लाठी मारी। वो टस तै मस कोन्या होया, ठाड्डा और पक्का होया चोर लाग्या। पर मनैं चाणचक उसकी गर्दन पकड़ ली। इतणे में बालक आगे और वो दबोच लिया।

-आच्छा रै रसीले, तमनै वो काबू कर लिया।

-हां, बढ़िया बात तो यो होई अक नौंवीं मिनट में पुलिस की गाड़ी आगी। पुलिस आळे बोले- 112 नंबर पै डायल तमनै कर्‌या था? बोलो के बात होई।

- पुलिस आळां ताहीं हामनै सारी घटना बताई। पुलिस नै वो माणस पकड़ लिया। पूछताछ करण का प्रयास कर्‌या, पर उस माणस नै ना तो जबान खोली और ना मोबाइल फोन का लॉक खोल्या। पक्का बदमाश था। इस्सा भी लागै था जाणू छिक्कै नशा कर्‌या था। फेर पुलिस उसनै थाने में ले गी।

- पक्का चोर-बदमाश। वो एकला नहीं था, इस बात का आगले दिन की रात नै जब बेरा पाट्‌या जिब रात नै इसै गाम की फिरनी पै दूसरे प्रदेश के नंबर की एक गाड़ी पकड़ी गई। रात नै तीन-तीन पुलिस की गाड़ियां नै उन बदमाशां का पीच्छा कर्‌या। हालांकि बदमाश उस टैम भाजण में कामयाब रहे। पर जै पुलिस की मदद ना मिलती तो वे या तो किसे के डांगर खोल ले जाते या किसे की कार या और कुछ सरका ले जाते।

-तो छबीले 112 नंबर पर डायल करण का यू सुख देख्या, एक फोन पै पुलिस की मदद मिलगी और चोरां का पड़गड़ास पाटग्या। टैम पै पुलिस ना आती तो होग्या था काम।

- बेरा सै पुलिस क्यूकर पहुंचै सै? 112 नंबर पर डायल करती हाणा फोन करण आळे नै आपणा नाम, पता और परेशानी बताणी हो सै। उसके बाद उसै एरिये की पुलिस उस फोन नंबर की लोकेशन सैट करकै ठिकाणे पै पहुंच ज्या सै।

-रसीले, पुलिस की यो तत्काल सेवा स्कीम इजराइल तैं आई सै। एकबै म्हारे सीएम मनोहर लाल उड़ै गए थे और उननै यो पुलिस सेवा देखी थी। बढ़िया लागी। उननै हरियाणा में आते ही इस सेवा की तैयारी कर दी और रातों-रात काम करवाकै लागू भी कर दी। इस स्कीम का फायदा यो होर्‌या सै, अक चोरी चकारी की घटना कम होगी। चोर उचक्कां नै बेरा पाटग्या अक थोड़ा सा भी रौळा माचग्या ना सीधे पुलिस के हाथां में जांगे।

-भाई छबीले 112 का नुकसान भी होर्‌या सै। मैं घर में जिब भी ठाडू बोलूं सूं तेरी भाभी 112 नंबर की धमकी देण लागज्या सै।

- भाई, उसनै समझा दिए अक 'ठाडू बोल' म्हारी संस्कृति का हिस्सा है, और इसमें गृहस्थी का रस भरा है।

- मनोज प्रभाकर

नसीब सिंह कुंडू

विरासत में मिली थी अभिनय और गायन प्रतिभा

हरियाणवी फिल्म 'चंद्रावल' में 'रूंडा' का हास्य किरदार निभाकर लोकप्रियता लूटने वाले कलाकार नसीब सिंह कुंडू को अभिनय और गायन प्रतिभा विरासत में मिली थी। इनके पूर्वज अल्लाह बक्श, कंदू और सुरंगन बादशाह अकबर के दरबार में साजिंदे थे और कोरस के रूप में गाया करते थे। उन्हीं के वंशज बदले खां उर्फ बदलूराम नवाबों के यहां लोकगीत और लोकगाथाएं सुनाते थे। बदलूराम के पुत्र जागेराम (नसीब के पिता) ने भी अपने भाइयों संग गाना शुरू कर दिया था।

रोहतक के गांव टिटोली में दो मई, 1961 को जन्में नसीब सिंह लोकसंपर्क विभाग भिवानी में कई वर्षों तक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी रहे। उन्हें नौकरी के दौरान ही फिल्म 'चंद्रावल' में अभिनय का मौका मिला और ये रातों रात स्टार कॉमेडियन बन गए।

नसीब सिंह कुंडू ने हरियाणवी फिल्म 'चंद्रावल' में रूंडा का, लाडो बसंती में अठन्नी का, गुलाबो में काले, जर, जोरू और जमीन में गबरू तथा जाटणी में धमलू पटवारी का किरदार बखूबी निभाया। फूल बदन में 'टाली' का रोल किया। गौरतलब है कि नसीब की आवाज में कई ऑडियो कैसेट रूण्डे खूण्डे की महफिल, रूंडे खूंडे की चौपाल, रूंडे खूंडे की हंसी की फुहार, मोल की लुगाई, रांडों का महासम्मेलन, ताजी बुढ़िया बासी बुढ़ा, नास की जड़, आज थारा फूफा आर्‌या आदि बाजार में धूम मचा चुकी हैं।

नसीब सिंह उम्दा गायक और संगीतकार भी थे। गायन का पहला मौका आल इंडिया रेडियो पर प्रसारित फरमाइशी कार्यक्रम में 1970 में मिला। इसमें इन्होंने कृष्ण जन्म की रागिनी गाई। आकाशवाणी के रोहतक, दिल्ली, शिमला और जालंधर केंद्रों तथा दूरदर्शन केंद्रों पर भी इन्होंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कमाल की बात यह है कि वे बोलने समय हकलाते थे लेकिन गाना गाते समय कभी नहीं हकलाए।

बीती 9 अगस्त, 2022 की रात नसीब सिंह कुंडू इस दुनिया को अलविदा कह गए।

-सुशील सैनी

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com